भारत का विभाजन --2

हिंदू पुनरुत्थानवादियों ने भी दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा किया। वे भारत पर मुसलमानों के पिछले शासन से नाराज़ थे। हिंदू पुनरुत्थानवादियों ने गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए रैली निकाली, जो मुसलमानों के लिए मांस का एक सस्ता स्रोत है। वे आधिकारिक लिपि को फ़ारसी से हिंदू देवनागरी लिपि में बदलना चाहते थे, जिससे प्रभावी रूप से उर्दू के बजाय हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के लिए मुख्य उम्मीदवार बनाया जा सके।

कांग्रेस ने अपनी नीतियों में कई गलतियाँ कीं, जिससे लीग को यह विश्वास हो गया कि औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के बाद अविभाजित भारत में रहना असंभव है क्योंकि उनके हितों को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। ऐसी ही एक नीति थी भारत के स्कूलों में “वंदे मातरम” की स्थापना, जो ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम विरोधी भावना से जुड़ा एक राष्ट्रगान है, जहाँ मुस्लिम बच्चों को इसे गाने के लिए मजबूर किया जाता था।

कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को समर्थन देने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि मुस्लिम लीग ने अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया था, जिसे अंग्रेजों का समर्थन मिला, जिन्हें बड़े पैमाने पर मुस्लिम सेना की मदद की जरूरत थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी की राजनीति से वापसी ने भी लीग को सत्ता हासिल करने में मदद की, क्योंकि उन्होंने उन प्रांतों में मजबूत मंत्रालय बनाए, जहां बड़ी मुस्लिम आबादी थी। उसी समय, लीग ने भारत में मुसलमानों से अधिक समर्थन हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया, खासकर जिन्ना जैसे गतिशील नेताओं के मार्गदर्शन में। अविभाजित भारत की कुछ उम्मीद थी, लेकिन 1942 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित अंतरिम सरकार को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने से मुस्लिम लीग के नेताओं को यकीन हो गया कि समझौता असंभव था और विभाजन ही एकमात्र रास्ता था।

विभाजन" - 14-15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान के दो अलग-अलग राज्यों में विभाजन - "अंतिम क्षण" का तंत्र था जिसके द्वारा ब्रिटिश इस बात पर सहमति बनाने में सक्षम थे कि स्वतंत्रता कैसे होगी । उस समय, बहुत कम लोग समझ पाए कि विभाजन क्या होगा या इसके परिणाम क्या होंगे, और इसके बाद बड़े पैमाने पर हुए पलायन ने समकालीन लोगों के विशाल बहुमत को आश्चर्यचकित कर दिया ।

राष्ट्रवादी गतिविधि का मुख्य माध्यम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसके सबसे प्रसिद्ध नेताओं में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे । 1940 के दशक से पहले भी, इसने एक मजबूत केंद्र के साथ एकात्मक राज्य के लिए लंबे समय तक तर्क दिया था ; भले ही कांग्रेस अपने उद्देश्यों में धर्मनिरपेक्ष थी, लेकिन अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन इस विचार को संदेह की दृष्टि से देखते थे, उनका मानना था कि इससे हिंदुओं का राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत होगा, जो आबादी का लगभग 80% हिस्सा थे।

अपनी आबादी के लगभग 25% के साथ, मुसलमान ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक थे। शाही शासन के तहत, वे आरक्षित विधायी सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली द्वारा अपनी अल्पसंख्यक स्थिति की रक्षा करने के आदी हो गए थे। राजनीतिक नियंत्रण की ब्रिटिश प्रणाली सहयोग करने के इच्छुक हित समूहों की पहचान करने पर निर्भर थी, एक शासन शैली जिसे अक्सर "फूट डालो और राज करो" के रूप में वर्णित किया जाता है।

स्वतंत्रता के करीब आने के साथ ही इस सुरक्षा को खोने की संभावना ने अधिक से अधिक मुसलमानों को चिंतित कर दिया, पहले उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंगाल और पंजाब के प्रभावशाली मुस्लिम-बहुल प्रांतों में। 1945-46 में, मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम वोटों का बहुमत जीता।

फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया - और अचानक, भारत में राजनीतिक दांव काफी बढ़ गये।

राज का अंत

जब 1939 में ब्रिटेन ने बिना किसी परामर्श के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया; बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन हुए, जिसकी परिणति 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हुई, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था। इसमें भाग लेने के कारण गांधी और नेहरू तथा हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1945 तक जेल में रखा गया।

इस बीच, स्थानीय सहयोगियों की ब्रिटिश युद्धकालीन ज़रूरत ने मुस्लिम लीग को भविष्य की राजनीतिक सुरक्षा के बदले में अपना सहयोग देने का मौक़ा दिया। मार्च 1940 में, मुस्लिम लीग के "पाकिस्तान" प्रस्ताव में भारतीय मुसलमानों को समायोजित करने के लिए "अलग-अलग राज्यों" - एकवचन नहीं, बल्कि बहुवचन - के निर्माण का आह्वान किया गया, जिनके बारे में उनका तर्क था कि वे एक अलग "राष्ट्र" थे।

इतिहासकार अभी भी इस बात पर विभाजित हैं कि यह अस्पष्ट मांग विशुद्ध रूप से सौदेबाजी का जवाब थी या एक दृढ़ उद्देश्य। लेकिन जबकि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मुद्दे को हल करना हो सकता है, इसने इसके बजाय इसे और बढ़ा दिया।

युद्ध के बाद, लंदन में एटली की लेबर सरकार ने माना कि ब्रिटेन की तबाह अर्थव्यवस्था, अति-विस्तारित साम्राज्य की लागत का सामना नहीं कर सकती। 1946 की शुरुआत में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, और एटली ने इसके मिशन का वर्णन महत्वाकांक्षी शब्दों में किया: "मेरे सहकर्मी भारत को जल्द से जल्द और पूरी तरह से आज़ादी दिलाने में मदद करने के लिए अपना पूरा प्रयास करने के इरादे से जा रहे हैं। वर्तमान शासन व्यवस्था की जगह किस तरह की सरकार आएगी, यह भारत को तय करना है; लेकिन हमारी इच्छा है कि हम उसे यह निर्णय लेने के लिए तुरंत तंत्र स्थापित करने में मदद करें।"

संसद के एक अधिनियम ने जून 1948 को सत्ता हस्तांतरण की समयसीमा के रूप में प्रस्तावित किया। लेकिन मिशन अपनी प्रस्तावित संवैधानिक योजना पर सहमति हासिल करने में विफल रहा, जिसमें एक ढीले संघ की सिफारिश की गई थी; इस विचार को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने किसी भी तरह से "पाकिस्तान" के लिए आंदोलन करने की कसम खाई ।